

प्रेषक,

डा0 एस0सी0 जोशी  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2007

विषय:- सूखे से प्रभावित क्षेत्र में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग के शासनादेश संख्या 380/XVIII(2)/2006 दिनांक 18.05.2006 द्वारा दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को रु0 8.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, तद्विषयक शासनादेश संख्या 1520/उन्तीस(2)/2006 दिनांक 31.07.2006 के क्रम में दैवीय आपदा के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के मरम्मत हेतु आपके पत्र संख्या 445/अप्रै-03/सूखा राहत कार्य/2007-08 दिनांक 25.04.2007 द्वारा शासन को प्रेषित रु0 51.50 लाख के प्राक्कलनों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्राक्कलनों के टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई कुल धनराशि रु0 48.60 लाख (रुपये अड़तालीस लाख साठ हजार मात्र) जिस हेतु प्राक्कलन में संबंधित मदों में पाई गई औचित्यपूर्ण सही धनराशि का विवरण संलग्न है, पर निम्नविवरणानुसार योजनावार प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही आपदा विभाग के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18.05.2006 द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 8.75 करोड़ में से निम्न शर्तों के अधीन व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रु0 लाख में)

जनपद	योजना का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	02	03
चमोली	(I) गोपेश्वर	14.00
"	(II) छिनका	11.70
"	(III) कर्णप्रयाग फेज-2	11.90
"	(IV) गुमार लगा गेरुड़	11.00
	योग-	48.60

(I) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर सम्बन्धित विभाग, विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

(II) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते हुए समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(III) कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(IV) कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गणित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायें एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाये एवं जिन आगणनों में रिलप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाये, तथा इसका सत्यापन अधि०अभि० स्वयं करें।

(V) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय इसी मद में किया जाये, एक मद की राशि दूसरें मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इस का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई का होगा।

(VI) प्र०वि० से स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नहीं हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

(VII) कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य विभागीय अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है, यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसका समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी जब इस बात की लिखित रूप से पुष्टि हो जाये कि उक्त विवरण सही एवं औचित्य पूर्ण है।

(VIII) दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्य करने की तिथि का आंकलन कर दिया जाये।

(IX) आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18.05.2006 में दी गई अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(डा० एम०सी० जोशी)

अपर सचिव

✓




पृ०स० 654 /उन्तीस(2)/07-(106पे०)/2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग।
3. संयुक्त सचिव, एन०डी०एम०, प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग 2/5
7. कोषाधिकारी, चमोली।
8. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के सज्ञानार्थ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ
- ✓ 10. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान पौड़ी।
12. गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

  
(नवीन सिंह तड़ागी)  
उप सचिव

शासनादेश संख्या 654/उन्तीस(2)/07-2(106पे0)/2006 दिनांक 27 अगस्त, 2007  
का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

जनपद	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनु0 लागत	स्वीकृत लागत में काटौती की गयी मदवार धनराशि का विवरण	मदवार अनु0 लागत	परीक्षणोपरान्त मदवार स्वीकृत लागत
01	02	03	04	05	06
चमोली	(I) गोपेश्वर	15.00	सीमेन्ट एवं स्टील, सहित सिविल कार्य की लागत जी0आई0 पाइप एवं विशेष की लागत	5.02 9.99	4.49 9.51
			योग (दशमलव के पहले स्थान तक पूर्णांकित)		14.00
"	(II) छिनका	12.00	सीमेन्ट एवं स्टील सहित सिविल कार्य की लागत जी0आई0 पाइप एवं विशेष की लागत	2.32 9.68	2.17 9.56
			योग (दशमलव के पहले स्थान तक पूर्णांकित)		11.70
"	(III) कर्णप्रयाग फेज-2	12.00	सामग्री के दुलान सहित सिविल कार्य की लागत पाइप एवं विशेष की लागत	3.68 8.34	3.60 8.30
			योग		11.90
"	(IV)गुमार लग्गा गेरुड़	12.50	सामग्री के दुलान सहित सिविल कार्य की लागत परन्तु सीमेन्ट की लागत छोड़ते हुए जी0आई0 पाइप एवं फिटिंग्स की लागत	6.22 6.28	4.78 6.21
			योग (दशमलव के पहले स्थान तक पूर्णांकित)		11.00
			(पूर्णांकित धनराशि का) महायोग		48.60

  
(नवीन सिंह तड़ागी)  
उप सचिव